अण्डमान निकोबार
द्वीप समाचार

रजि.न.34300/80 | संख्या 10 | श्री विजय पुरम, शनिवार , 10 जनवरी 2026 | web: dt.andamannicobar.gov.in | 2.00 रूपए

112 Emergency Response Support System
One India, One Emergency Number 112

ननकौड़ी में द्वीप पर्यटन उत्सव का आयोजन

कमोर्टा, 9 जनवरी

निकोबार द्वीपसमूह की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक कला रूपों और जीवंत सामुदायिक जीवन का जश्न मनाते हुए, 7 और 8 जनवरी, 2026 को इंदिरा पार्क, ननकौड़ी में द्वीप पर्यटन महोत्सव (आईटीएफ) 2025 का आयोजन किया गया था। इस उत्सव ने सांस्.तिक अभिव्यक्ति, युवाओं की भागीदारी और अंतर–ग्राम आदान–प्रदान के लिए एक गतिशील मंच प्रदान किया, जिसमें ननकौड़ी द्वीपसमूह के निवासियों की उत्साहपूर्ण भागीदारी हुई।

इस महोत्सव का आयोजन नैनकौड़ी प्रशासन द्वारा सूचना, प्रचार और पर्यटन विभाग और कला और संस्कृति विभाग, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के सहयोग से, स्थानीय जनजातीय परिषदों के सहयोग से किया गया था।

उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्री आदित्य संगोत्रा, सहायक आयुक्त, ननकौड़ी उपस्थित थे। श्री चार्ल्स जैकब, अध्यक्ष, जनजातीय परिषद, कमोर्टा, श्रीमती आयशा मजीद, अध्यक्ष, जनजातीय परिषद, ननकौड़ी और आईएनएस कारदीप और आईसीजी कमोर्टा के अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई।

कमोर्टा जनजातीय परिषद के अंतर्गत मुनक गांव के ग्रामीणों द्वारा प्रस्तुत पारंपरिक निकोबारी कला रूप "किंथवाका" पर एक वीडियो फिल्म प्रदर्शित की गई, जिसमें निकोबार द्वीपसमूह की सांस्कृतिक गहराई और जीवित परंपराओं का प्रदर्शन किया गया। इसके बाद मुख्य अतिथि सम्बोधित किया, जिसमें उन्होंने क्षेत्र में प्रशासन द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों पर प्रकाश डाला और पाइपलाइन में प्रमुख विकास परियोजनाओं का विवरण भी साझा किया, जो समावेशी और सतत विकास पर प्रशासन के निरंतर फोकस को दर्शाता है।

समारोह के दौरान, मुख्य अतिथि ने औपचारिक रूप से एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना (आईटीडीपी) के तहत खरीदी गई मोर्च्युरी वैन की चाबियां कमोर्टा और ननकौड़ी की जनजातीय परिषदों के अध्यक्ष को सौंपीं। इन वाहनों के प्रावधान ने जनजातीय समुदाय की लंबे समय से लंबित मांग को संबोधित किया, और इस पहल को एक संवेदनशील और जन–केंद्रित हस्तक्षेप के रूप में व्यापक रूप से सराहा गया, जो लंबे समय से चली आ रही सामुदायिक आवश्यकता की पूर्ति को दर्शाता है।

श्री मोहम्मद यूनुस एम., नोडल अधिकारी (आईटीएफ)/खंड विकास अधिकारी, ननकौड़ी ने अपने संबोधन में इस बात पर प्रकाश डाला कि ऐसे मंच सामुदायिक संबंधों को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण हैं और जनता को विभागीय भागीदारी के माध्यम से विभिन्न सरकारी योजनाओं और कल्याण कार्यक्रमों के बारे में जानने के लिए मूल्यवान अवसर भी प्रदान करते हैं।

शेष पृष्ठ 4 पर

द्वीप समुद्री भोजन महोत्सव–2026 का आयोजन

श्री विजय पुरम, 9 जनवरी

मत्स्य पालन विभाग, सूचना, प्रचार और पर्यटन विभाग, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के सहयोग से और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (एनएफडीबी), हैदराबाद के वित्तीय सहयोग से 15 और 16 जनवरी को मरीना पार्क स्ट्रेच रोड, श्री विजय पुरम में "द्वीप समुद्री भोजन महोत्सव –2026" का आयोजन कर रहा है, जिसमें अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह में ट्यूना क्लस्टर विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

दो दिवसीय उत्सव की कल्पना द्वीप की समृद्ध समुद्री संपदा और मत्स्य पालन आधारित आजीविका के एक जीवंत उत्सव के रूप में की गई है। इसका उद्देश्य मछुआरों, उद्यमियों, वैज्ञानिकों, रसोइयों, पर्यटकों और आम जनता को "समुद्र से प्लेट तक" समुद्री भोजन की यात्रा का अनुभव करने के लिए एक आम मंच पर लाना है। 2026 की थीम "सभी के लिए सुरक्षित, पौष्टिक और टिकाऊ समुद्री भोजन" पर केंद्रित है।

महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों, लाइव सीफूड खाना पकाने के प्रदर्शन, सार्वजनिक प्रतियोगिताओं, इंटरैक्टिव सत्र, पारंपरिक मछली नाव रेसिंग और प्रतिष्ठित पुरूष और महिला शेफ प्रतियोगिता सहित गतिविधियों की एक रोमांचक श्रृंखला शामिल होगी, जहां समापन दिवस पर शीर्ष तीन विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। यह आयोजन द्वीपों की पाक उत्कृष्टता, पारंपरिक ज्ञान और टिकाऊ मछली पकड़ने की प्रथाओं को उजागर करने के लिए तैयार किए गए हैं।

महोत्सव के दौरान, जीवित, ताजी, ठंडी और जमी हुई मछली, मूल्य वर्धित मछली उत्पाद, समुद्री खाद्य व्यंजन, एक्वैरियम, मछली फ़ीड, आवश्यक मत्स्य पालन आवश्यकताएं और खेल मछली पकड़ने की सेवाओं सहित विभिन्न मछली पकड़ने से संबंधित गतिविधियों, उत्पादों/सेवाओं को प्रदर्शित करने के लिए इच्छुक मत्स्य पालन संघों/उद्यमियों/मछली सहकारी समितियों/एक्वैरियम दुकानों/होटलों और रेस्तरां, महिला स्व–सहायता समूहों (एसएचजी), एनजीओ वगैरह को स्टॉल आवंटित किए जाएंगे। स्टॉल आवंटन के संबंध में विवरण चयनित आवेदकों को उचित समय पर सूचित किया जाएगा।

मत्स्य पालन विभाग की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि इच्छुक व्यक्ति और कंपनियां निर्धारित प्रारूप में अपने आवेदन 12 जनवरी, 2026 तक या उससे पहले मत्स्य पालन प्रशिक्षण केंद्र, मरीन हिल या ईमेल (fisheriestrainingcentreani@gmail.com) पर जमा कर सकते हैं। आवेदन प्रारूप मत्स्य पालन प्रशिक्षण केंद्र, मरीन हिल से प्राप्त किया जा सकता है या https://andamannicobar.gov.in/ और https://anifisheries.andamannicobar.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए, आवेदक 9594801891/8900942618 पर संपर्क कर सकते हैं।

ननकौड़ी में मोर्च्युरी वैन की चाबियां सौंपी

ननकौड़ी, 9 जनवरी

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन की ओर से, सहायक आयुक्त, ननकौड़ी श्री आदित्य संगोत्रा ने कल इंदिरा पार्क, कमोर्टा में आयोजित द्वीप पर्यटन महोत्सव 2025 के दौरान ग्राम प्रधानों और जनजातीय परिषदों के सदस्यों की उपस्थिति में कामोर्टा और ननकौड़ी की जनजातीय परिषद के अध्यक्ष को औपचारिक रूप से मोर्च्युरी वैन की चाबियाँ सौंपी।

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव डॉ. चंद्र भूषण कुमार (आईएएस) को सभी जनजातीय परिषदों से यह मांग मिली थी। उनके मार्गदर्शन और समय पर हस्तक्षेप पर कार्रवाई करते हुए, जिला प्रशासन ने खरीद प्रक्रिया शुरू की, जिसका समापन आईटीएफ 2025 के दौरान कमोर्टा और ननकौड़ी द्वीपों के लिए मोर्च्युरी वैन के प्रावधान और औपचारिक हस्तांतरण के रूप में हुआ।

ग्राम कप्तानों और जनजातीय परिषदों के सदस्यों ने एक महत्वपूर्ण सामुदायिक आवश्यकता को संबोधित करने और जनजातीय आबादी की लंबे समय से लंबित आकांक्षा को पूरा करने के लिए मुख्य सचिव, सचिव (आदिवासी कल्याण) और निकोबार जिले के उपायुक्त के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया। यह याद किया जा सकता है कि कछाल और चावरा द्वीपों के लिए मोर्च्युरी वैन पहले खरीदी गई थीं और स्वतंत्रता दिवस–2025

शेष पृष्ठ 4 पर

मसाला प्रवाह के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं से परिवर्तनकर्ता की भूमिका निभाने का आह्वान

समुदाय आधारित मसाला उद्यान और विपणन सुविधा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण जैसी नई पहलें प्रस्तावित

मायाबंदर, 9 जनवरी।

श्रीमती पल्लवी सरकार (आईएएस), सचिव (कृषि एवं पशुपालन तथा पशु चिकित्सा सेवाएं), अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन ने 8 एवं 9 जनवरी, 2026 को मायाबंदर और रंगत क्षेत्रों का दौरा कर मसाला प्रवाह कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की। यह समीक्षा उत्तर व मध्य अण्डमान के उपायुक्त तथा रंगत के सहायक आयुक्त की उपस्थिति में की गई, जिन्होंने समयबद्ध कार्यान्वयन एवं समन्वय के लिए क्षेत्रीय कर्मियों को आवश्यक निदेश भी दिए।

इस दौरान सचिव ने पीआरआई प्रतिनिधियों, ग्राम प्रधानों, स्वयं सहायता समूह के सदस्यों एवं प्रगतिशील किसानों से संवाद किया तथा किसानों के समक्ष आ रही चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा कर उनके समाधान को समयबद्ध रूप से सुनिश्चित करने पर बल दिया।

किसान मैपिंग, पंजीकरण और बाजार संपर्क पर विशेष जोर

अपने संबोधन में सचिव ने कहा कि मसाला प्रवाह एक किसान–केंद्रित कार्यक्रम है और ग्राम प्रधानों से स्थानीय स्तर पर परिवर्तनकर्ता की भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं से किसान मैपिंग एवं निःशुल्क ऑनलाइन किसान पंजीकरण पोर्टल पर व्यापक नामांकन के लिए सक्रिय सहयोग करने का आग्रह किया, जिससे कार्यक्रम के अंतर्गत विपणन सहायता, एकत्रीकरण तथा मूल्य–श्रृंखला योजना को सुदृढ़ किया जा सके।

उन्होंने बताया कि अब तक केंद्र शासित प्रदेश में 103.5 हेक्टेयर क्षेत्र में मसाला बागानों को शामिल किया गया है, जिससे लगभग 700 किसानों को लाभ मिला है।

अभिसरण दृष्टिकोण से सामुदायिक मसाला उद्यान

सचिव ने वैज्ञानिक खेती पद्धतियों के महत्व पर प्रकाश डाला, जिसमें मौजूदा नारियल एवं सुपारी बागानों में मसालों की अंतरफसली खेती, मूल्य संवर्धन तथा संरचित बाजार संपर्क के माध्यम से किसानों की आय को सतत् रूप से बढ़ाने पर जोर दिया गया। उन्होंने पीआरआई से उपयुक्त सामुदायिक भूमि की पहचान कर मसाला खेती क्लस्टर अथवा सामुदायिक मसाला उद्यान विकसित करने का भी आग्रह किया तथा अवसंरचना निर्माण एवं विस्तार के लिए ग्रामीण विकास योजनाओं के साथ अभिसरण का आश्वासन दिया।

आदान प्रबंधन एवं क्षेत्र निरीक्षण

उर्वरकों की उपलब्धता को लेकर उठी चिंताओं पर सचिव ने बताया कि यह समस्या शीघ्र ही सुलझा ली जाएगी। उन्होंने किसानों को स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए रासायनिक उर्वरकों का विवेकपूर्ण उपयोग करने की सलाह दी। दौरे के दौरान सचिव ने विभागीय फार्मों एवं मसाला प्रवाह पहल में शामिल प्रगतिशील किसानों के खेतों का निरीक्षण कर क्षेत्रीय प्रदर्शन का आकलन किया तथा जिले में मसाला खेती एवं प्रसंस्करण की आगे की संभावनाओं पर विचार किया।

संपर्क से समाधान–प्रशासन गांव की ओर के तहत जन शिकायत निवारण कार्यक्रम सह राजस्व शिविर न्यायालय आयोजित

मायाबंदर, 9 जनवरी

उत्तर व मध्य अण्डमान ज़िला प्रशासन द्वारा "संपर्क से समाधान–प्रशासन गांव की ओर" पहल के अंतर्गत जन शिकायत निवारण कार्यक्रम–सह–राजस्व शिविर न्यायालय का आयोजन 9 जनवरी, 2026 को पोखाडेरा सामुदायिक भवन, मायाबंदर में किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री सुशांत पधा (आईएएस), उपायुक्त, उत्तर व मध्य अण्डमान ने की तथा संबंधित लाइन विभागों के समन्वय से इसका संचालन किया गया। इस संयुक्त कार्यक्रम का उद्देश्य सेवा वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करना, जन शिकायतों का समयबद्ध निवारण सुनिश्चित करना तथा जमीनी स्तर पर आम जनता से प्रत्यक्ष संवाद के माध्यम से राजस्व से संबंधित मामलों का मौके पर ही निस्तारण करना था।

इस दौरान कुल 34 राजस्व मामलों का निपटारा किया गया, जिनमें 12 उप–मंडल मामलों, 17 नाम सुधार मामलों तथा 5 नामांतरण मामले शामिल थे। कार्यक्रम में लगभग 110 लोगों ने भाग लिया, जिनमें पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के प्रतिनिधि, विभागाध्यक्ष तथा आम जनता के सदस्य शामिल थे। संवाद के दौरान कई जन शिकायतें सामने आईं, जिनमें ज़िला अस्पताल मायाबंदर में रक्त बैंक की अनुपलब्धता, अस्पताल के शवगृह कक्ष की जर्जर स्थिति, सब्जियों एवं मछलियों की कीमतों में वृद्धि तथा बिल्लीग्राउंड में कोल्ड फूड स्टोरेज सुविधा के निर्माण की आवश्यकता प्रमुख थीं। उपायुक्त (उत्तर व मध्य अण्डमान) ने संबंधित विभागों को इन मुद्दों की प्राथमिकता के आधार पर परीक्षण करने के निदेश दिए गए।

"संपर्क से समाधान–प्रशासन गांव की ओर" पहल उत्तर व मध्य अण्डमान ज़िले में सहभागी शासन को सुदृढ़ करने तथा जन सेवाओं की प्रभावी, संवेदनशील एवं उत्तरदायी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निरंतर जारी है।

जिला परिषद अध्यक्ष का निरीक्षण दौरा

श्री विजय पुरम, 9 जनवरी

दक्षिण अण्डमान जिला परिषद के अध्यक्ष श्री प्रकाश अधिकारी ने बृंदाबन निर्वाचन क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य श्री अब्दुल अजीज और इंजीनियरिंग विंग के अधिकारियों के साथ आज विम्बर्लीगंज में चिल्ड्रन पार्क का निरीक्षण किया। इसके बाद, अध्यक्ष ने बम्बूफ्लाट में नवनिर्मित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और जिला परिषद विवेकानन्द केन्द्र विद्यालय, शोरपॉइंट का दौरा किया। इसके अलावा, उन्होंने पोर्ट मोट स्थित विवेकानंद केंद्र जिला परिषद विद्यालय में सभागार के चल रहे निर्माण कार्य और मौजूदा बुनियादी ढांचे का भी निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान अध्यक्ष ने कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों और कार्यकारी एजेंसियों को गुणवत्ता और निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करते हुए शेष कार्यों को पूरा करने और चिह्नित कमियों को प्राथमिकता के आधार पर दूर करने का निर्देश दिया। उन्होंने इंजीनियरिंग विंग को जल्द से जल्द विवेकानंद केंद्र जिला परिषद विद्यालय, पोर्ट मोट में स्कूल के बुनियादी ढांचे की मरम्मत और रखरखाव के लिए एक व्यापक अनुमान तैयार करने का निर्देश दिया।

दक्षिण अण्डमान जिला परिषद की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह दौरा छात्रों और स्थानीय आबादी के लाभ के लिए विकास कार्यों को समय पर पूरा करने और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए दक्षिण अण्डमान जिला परिषद की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

गुरू शिष्य हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम

श्री विजय पुरम, 9 जनवरी

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित गुरु–शिष्य हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम (जीएसएचपीपी) का आज सुबह हैडो स्थित फॉरेस्ट क्लब हॉल में उद्घाटन किया गया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम हस्तशिल्प सेवा केंद्र, श्री विजय पुरम द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। उद्घाटन कार्यक्रम में चयनित 30 महिला हस्तशिल्प कारीगरों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री टी. विजय, आईआईएस, मीडिया एवं संचार अधिकारी, प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) ने की, जो मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। अपने संबोधन में श्री टी. विजय ने प्रतिभागियों को अपने कौशल में वृद्धि करने तथा प्रशिक्षण को आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ाने के माध्यम के रूप में उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने देश भर में स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने और महिला कारीगरों को सहयोग प्रदान करने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं।

प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए श्री के. कुमारवेल, सहायक निदेशक, हस्तशिल्प सेवा केंद्र, श्री विजय पुरम ने कारीगरों को प्रशिक्षण में सक्रिय रूप से भाग लेने और कॉयर हस्तशिल्प सीखने

के इस अवसर का भरपूर लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया।

यहाँ प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इससे पहले कार्यक्रम की शुरुआत मास्टर क्राटपर्सन श्रीमती कमला के स्वागत भाषण से हुई। गुरु–शिष्य हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य पारंपरिक शिल्पों का संरक्षण करना तथा संरचित कौशल विकास के माध्यम से महिला कारीगरों को सशक्त बनाना है, जिससे अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में सतत रोजगार और समावेशी विकास को बढ़ावा मिले।

कृत्रिम गर्भाधान पर जागरूकता कार्यक्रम

श्री विजय पुरम, 9 जनवरी

पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग, विम्बर्लीगंज द्वारा 7 जनवरी को ग्राम पंचायत हॉल, विम्बर्लीगंज में कृत्रिम गर्भाधान पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। निदेशक, पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवा ने विभाग के अधिदेश के बारे में बात की और पशु चिकित्सा सेवाओं पर किसानों की प्रतिक्रिया मांगी। उन्होंने बेहतर पशु स्वास्थ्य और उत्पादकता के लिए संतुलित राशन के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने द्वीपों में ताजा गाय के दूध की बढ़ती मांग पर जोर दिया, जिसे केवल एआई के माध्यम से उच्च उपज देने वाली गायों को विकसित करके ही पूरा किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि सेक्स–सॉर्टेड वीर्य एआई न केवल वांछित मादा बछड़ों के जन्म को सुनिश्चित करता है बल्कि नर बछड़े की आबादी को कम करने में भी मदद करता है। उन्होंने भ्रूण स्थानांतरण प्रौद्योगिकी के बारे में विस्तार से बताया, जिसके माध्यम से कम से कम समय में वांछित मादा बछड़े पैदा किए जा सकते हैं।

विम्बर्लीगंज, कन्यापुरम और मन्नारघाट के प्रधानों ने भी किसानों को संबोधित किया और उनसे पशु स्वास्थ्य और दूध उत्पादन में सुधार के लिए विभाग के साथ सहयोग करने का आग्रह किया। पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवा विभाग की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि अपने संबोधन में, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, विम्बर्लीगंज ने कृत्रिम गर्भाधान (एआई) के महत्व और डेयरी उद्योग को बदलने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया।

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत प्रशिक्षण

श्री विजय पुरम, 9 जनवरी

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत "सतत सामुदायिक विकास के लिए ग्रामीण युवाओं और पंचायती राज संस्थानों के बीच तालमेल को बढ़ावा देना" विषय पर एक दिवसीय ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम कल पंचायत सम्मेलन हॉल, ग्राम पंचायत सुभाषग्राम, डिगलीपुर में आयोजित किया गया था।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रधानों, उप–प्रधानों और स्थानीय ग्रामीण युवाओं की सक्रिय भागीदारी देखी गई, जिसका लक्ष्य जमीनी स्तर के विकास के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों और युवाओं के बीच एक मजबूत सहयोगी ढांचा तैयार करना है। सत्र सतत सामुदायिक विकास, मॉडल गांव अवधारणाओं, युवाओं के नेतृत्व वाली समूह गतिविधियों और पंचायत स्तर पर भागीदारी योजना पर केंद्रित था। बीडीओ, डिगलीपुर की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि डोमेन विशेषज्ञों और संसाधन व्यक्तियों ने स्थानीय जरूरतों की पहचान करने और विकास पहलों को प्रभावी ढंग से लागू करने में पीआरआई और ग्रामीण युवाओं के बीच समन्वित प्रयासों के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में स्थानीय युवाओं के लिए सरकारी योजनाओं का अवलोकन भी शामिल किया गया, जिससे उन्हें सामुदायिक विकास में नेतृत्वकारी भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। एक इंटरैक्टिव चर्चा और फीडबैक सत्र ने प्रशिक्षण के समापन को चिह्नित किया, जिससे प्रतिभागियों को विचार और अनुभव साझा करने का अवसर मिला।

53वें सुभाष मेला का आयोजन

श्री विजय पुरम, 9 जनवरी

यहां प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती के उपलक्ष्य में 23 से 29 जनवरी तक कृष्णा नगर, स्वराज द्वीप में 53वां सुभाष मेला आयोजित किया जाएगा।

डंडस प्वाइंट की वाहन फेरी सेवा

श्री विजय पुरम, 9 जनवरी

जहाज़रानी सेवा निदेशालय की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि प्रशासनिक कारणों से, चाथम से डंडस प्वाइंट तक 2.15 बजे निर्धारित एमवीएफ ऑस्टिन–3 की वाहन फेरी सेवा को 9 जनवरी से अगले आदेश तक निलंबित कर दिया गया है।

विज्ञान, कला और शिल्प प्रदर्शनी

श्री विजय पुरम, 9 जनवरी

सेंट मैरी स्कूल, मोहनपुरा ने 8 और 9 जनवरी 2026 को शैक्षणिक वर्ष 2025–26 के लिए अपनी विज्ञान, कला और शिल्प प्रदर्शनी "मेराकी 2.0" का सफलतापूर्वक आयोजन किया। प्रदर्शनी ने युवा मस्तिष्क को अपनी रचनात्मकता, नवाचार और व्यावहारिक सीखने का प्रदर्शन करने के लिए एक प्रेरक मंच प्रदान किया। कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन भातूबस्ती स्कूल के प्रिंसिपल श्री जे. डी. पुष्पराज ने किया, जिन्होंने अनुभवात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने में छात्रों और शिक्षकों के प्रयासों की सराहना की। सेंट मैरी स्कूल के प्रिंसिपल से प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्राथमिक अनुभाग के छात्रों की लाइव प्रस्तुति थी, जिन्होंने टिकाऊ जीवन के सार और इसके लाभों पर खूबसूरती से प्रकाश डाला। उच्च कक्षाओं के छात्रों ने स्थिरता पर नवीन विज्ञान परियोजनाओं का प्रदर्शन किया, कामकाजी और गैर–कामकाजी मॉडल के माध्यम से विचारशील विचार प्रस्तुत किए। "बेस्ट आउट ऑफ़ वेस्ट" थीम को समर्पित एक विशेष क्राट रूम में पुनर्चक्रण योग्य सामग्रियों से बने प्रभावशाली प्रदर्शन प्रदर्शित किए गए, जो पुनः उपयोग और संरक्षण का संदेश फैलाते हैं। प्रदर्शनी को आगंतुकों से जबरदस्त सराहना मिली।

ननकौड़ी में मोर्च्युरी वैन की चाबियां

पृष्ठ 1 का शेष

के अवसर पर संबंधित जनजातीय परिषदों को सौंप दी गई थीं, जो निकोबार जिले में जनजातीय कल्याण के लिए प्रशासन की लगातार प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

सहायक आयुक्त (नानकॉरी) की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस पहल का उद्देश्य आवश्यक सेवाओं को मजबूत करना, आदिवासी समुदायों की गरिमा को बनाए रखना और उनकी सांस्कृतिक प्रथाओं और परंपराओं के लिए उचित सम्मान सुनिश्चित करना है, जो शासन के लिए प्रशासन के जन–केंद्रित और सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील .ष्टिकोण की पुष्टि करता है।

ननकौड़ी में द्वीप पर्यटन उत्सव

पृष्ठ 1 का शेष

त्योहार समारोह के हिस्से के रूप में, सामूहिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने और स्वदेशी मनोरंजक प्रथाओं को पुनर्जीवित करने के लिए कई पारंपरिक सामुदायिक खेल और गतिविधियाँ आयोजित की गईं। इनमें पिलो फाइट (पुरुष), रस्साकशी और कोकोनट ग्रेटिंग शामिल हैं। इसके अलावा, हेलीपैड से इंदिरा पार्क तक एक मिनी मैराथन आयोजित की गई, जिसमें युवाओं और समुदाय के सदस्यों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई।

सांस्कृतिक संध्याओं में प्रदर्शनों की एक भव्य श्रृंखला देखी गई, जिसमें पारंपरिक, शास्त्रीय, लोक, अर्ध–शास्त्रीय, बॉलीवुड और पश्चिमी नृत्य शैलियों का जीवंत मिश्रण शामिल था। प्रमुख आकर्षणों में टीम तपोंग द्वारा अग्नि नृत्य और बांस नृत्य शामिल है, जो पारंपरिक आदिवासी ताकत और लय को दर्शाता है, चैंपिन और हितुई गांवों के ग्रामीण समूहों द्वारा लोक नृत्य, यूथ क्लब पिलपिलो और अन्य सामुदायिक समूहों द्वारा प्रदर्शन और विकास नृत्य अकादमी, श्री विजय पुरम के सांस्कृतिक दल के सदस्यों द्वारा शास्त्रीय और संलयन प्रदर्शन, जिन्होंने अपने उच्च–ऊर्जा और मनोरम प्रदर्शन के साथ कार्यक्रम के समग्र मानक को ऊंचा किया। स्कूली बच्चों के विभिन्न समूह और एकल प्रदर्शनों ने भी सांस्कृतिक संध्याओं में जीवंतता जोड़ दी। रंग–बिरंगे परिधानों, लयबद्ध ताल और अभिव्यंजक कहानी कहने वाले विविध प्रदर्शनों को दर्शकों ने गर्मजोशी से सराहा और ननकौड़ी द्वीपसमूह की सांस्कृतिक बहुलता को खूबसूरती से दर्शाया।

उत्सव के दूसरे दिन, सांस्कृतिक कार्यक्रम में कैरोल गायन प्रतियोगिता और ननकौड़ी आइडल–सीज़न 3 गायन प्रतियोगिता

सहित प्रतिस्पर्धी कार्यक्रम शामिल थे, जिसने स्थानीय गायकों और उभरती प्रतिभाओं के लिए एक मंच प्रदान किया। प्रतियोगिताओं में उत्साहपूर्ण भागीदारी और दर्शकों की मजबूत भागीदारी देखी गई, जिससे आईटीएफ 2025 की उत्सव भावना और समृद्ध हुई।

कृषि, पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवा, स्वास्थ्य, अग्निशमन सेवा और ग्रामीण विकास जैसे विभिन्न विभागों द्वारा स्थापित स्टालों ने आगंतुकों को आकर्षित किया और सरकारी योजनाओं, कल्याणकारी पहलों और आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं पर प्रभावी जागरूकता मंच के रूप में काम किया।

बीडीओ, ननकौड़ी की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि द्वीप पर्यटन महोत्सव 2025 एक उच्च नोट पर संपन्न हुआ, क्योंकि ननकौड़ी साझा बंधन, खुशी और सामूहिक खुशी के साथ जीवंत हो गया, जिससे लोगों के बीच एकता, सांस्तिक गौरव और सामुदायिक सद्भाव की भावना मजबूत हुई।

निकोबार जिले में तपेदिक उन्मूलन के लिए जनजातीय परिषद के साथ बैठक

कार निकोबार, 9 जनवरी

निकोबार जिले में कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर चर्चा करने के लिए आज जनजातीय परिषद, बिग लपाती, कार निकोबार में वयस्क बीसीजी टीकाकरण कार्यक्रम पर एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जनजातीय परिषद के अध्यक्ष श्री लियोनाल्ड निकोमेड और सचिव श्री मार्टिन लूथर ने की और इसमें सभी ग्राम प्रधान, महिला प्रतिनिधि और जनजातीय परिषद, कार निकोबार के सदस्यों ने भाग लिया।

चर्चा आगामी वयस्क बीसीजी टीकाकरण अभियान पर केंद्रित थी, जो तपेदिक उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान के हिस्से के रूप में निकोबार जिले में 15 जनवरी 2026 से शुरू होने वाला है। कमजोर वयस्क आबादी के बीच टीबी के खतरे को कम करने के लिए वयस्क बीसीजी टीकाकरण को एक महत्वपूर्ण निवारक हस्तक्षेप के रूप में पहचाना गया है। बैठक में जिला टीबी अधिकारी (एन) डॉ अनवर मूसा के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ श्री रमेश राव, जिला कार्यक्रम समन्वयक और श्री सुरेश कुमार, वरिष्ठ उपचार पर्यवेक्षक (एसटीएस) ने भाग लिया। डॉ. अनवर मूसा ने सदस्यों को तपेदिक, इसके प्रकार, संचरण के तरीके, निवारक उपायों और उपचार विकल्पों के बारे में जानकारी दी और कार निकोबार में वयस्क बीसीजी टीकाकरण अभियान को लागू करने के लिए प्रस्तावित योजना की रूपरेखा भी बताई।

जनजातीय परिषद के सदस्यों ने विचार–विमर्श में सक्रिय रूप से भाग लिया और कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के लिए अपने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। परिषद ने कार निकोबार के अंतर्गत विभिन्न गांवों में सामुदायिक हॉलों में वयस्क बीसीजी टीकाकरण सत्र आयोजित करने के लिए सामुदायिक भागीदारी को सुविधाजनक बनाने और संगठित करने के लिए विलेज फर्स्ट कैप्टन को निर्देश देकर समर्थन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। जनजातीय परिषद ने वयस्क बीसीजी टीकाकरण अभियान के सुचारू और प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए समन्वय, सामुदायिक गतिशीलता और स्थानीय सुविधा के संदर्भ में स्वास्थ्य कर्मचारियों को सक्रिय समर्थन का आश्वासन दिया।

समग्र शिक्षा योजना के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम

श्री विजय पुरम, 9 जनवरी

समग्र शिक्षा योजना के तहत जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (डीआईईटी), गाराचरामा, श्री विजय पुरम ने 5 से 7 जनवरी तक राजकीय बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में नौ शैक्षणिक क्षेत्रों के शिक्षकों के लिए 'विकलांग बच्चों की शिक्षा में फाउंडेशन कोर्स (एफसीईसीडी) पूरा करने वाले सामान्य शिक्षकों के लिए समावेशी शिक्षा' पर तीन दिवसीय क्षमता विकास कार्यक्रम आयोजित किया।

समापन सत्र में, मुख्य अतिथि के रूप में राज्य शिक्षा संस्थान/डाइट की प्रिंसिपल श्रीमती संगीता चंद ने समावेशी शिक्षा के लिए अपने कौशल को बढ़ाने के लिए भाग लेने वाले शिक्षकों के समर्पण और प्रतिबद्धता की सराहना की।

डाइट की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि मुख्यभूमि के संसाधन व्यक्तियों, प्रोफेसर रामा और श्रीमती श्री प्रिया, प्रभारी

निदेशक, एनआईईपीवीडी, चेन्नई ने समावेशी शैक्षणिक प्रथाओं, सीखने के लिए सार्वभौमिक डिजाइन (यूडीएल), व्यक्तिगत समर्थन रणनीतियों और नियमित कक्षाओं में विकलांग बच्चों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए सहयोगात्मक दृष्टिकोण पर व्यावहारिक सत्र दिए।

रंगत में श्रम विभाग द्वारा जागरूकता व पंजीकरण शिविर आयोजित

श्री विजय पुरम, 10 जनवरी

विभिन्न सामाजिक सुरक्षा सहायता योजनाओं के विस्तार के अपने वचन को सभी पात्र लाभार्थी श्रमिकों तक पहुँचाने के उद्देश्य से, लाभार्थी पंजीकरण अधिकारी/सहायक श्रम आयुक्त, रंगत के कार्यालय द्वारा स्थानीय पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के सहयोग से मध्य अण्डमान के भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों के लाभ हेतु 9 एवं 10 जनवरी, 2026 को क्रमशः उत्तरा एवं कदमतला ग्राम पंचायतों में 'जागरूकता सृजन–सह–पंजीकरण शिविर' का आयोजन किया गया। उद्घाटन सत्र कल मध्य अण्डमान के ग्राम पंचायत उत्तरा के सामुदायिक भवन में आयोजित किया गया।

यहाँ प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, श्रीमती सीता माझी, प्रमुख, पंचायत समिति, रांगट, मध्य अंडमान इस अवसर पर मुख्य अतिथि थीं। कार्यक्रम में लगभग 100 भवन निर्माण श्रमिकों ने भाग लिया। श्री सुरंजन मुखोपाध्याय, लाभार्थी पंजीकरण अधिकारी/सहायक श्रम आयुक्त, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन, उत्तर एवं मध्य अंडमान ने अपने संबोधन में बताया कि अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन ने वर्ष

2009 में एएनआई बीओसीडब्ल्यू वेलफेयर बोर्ड का गठन किया था तथा अब तक एएनआई बीओसीडब्ल्यू वेलफेयर बोर्ड द्वारा विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत पात्र लाभार्थी श्रमिकों को डीबीटी माध्यम से कुल 36.16 करोड़ रुपये की राशि वितरित की जा चुकी है। बीआरओ/एएलसी ने निर्माण श्रमिकों एवं आम जनता द्वारा मौके पर उठाए गए विभिन्न प्रश्नों का भी संतोषजनक उत्तर दिया।

कौशल विकास कार्यक्रम का आयोजन

श्री विजय पुरम, 9 जनवरी

उद्योग निदेशालय, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन ने 23 दिसंबर, 2025 से 9 जनवरी, 2026 तक गुप्तापाड़ा ग्राम पंचायत, दक्षिण अण्डमान में "हस्तशिल्प (नारियल के खोल, लकड़ी और बेंत और बांस उत्पाद)" पर 15 दिवसीय अल्पकालिक कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया।

कार्यक्रम का समापन समारोह आज पीआरआई सदस्यों की उपस्थिति में आयोजित किया गया, जिसमें ग्राम पंचायत गुप्तापाड़ा के प्रधान श्री दुर्लभ दास मुख्य अतिथि थे। स्वरोजगार को बढ़ावा देने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से हस्तशिल्प निर्माण में बुनियादी कौशल और तकनीकी जानकारी हासिल करने के लिए कुल 22 प्रशिक्षुओं ने कार्यक्रम में भाग लिया।

सभा को संबोधित करते हुए उद्योग निदेशालय के उप निदेशक श्री मोहम्मद इशाक ने विभिन्न विभागीय योजनाओं और पहलों पर प्रकाश डाला जो प्रशिक्षण कार्यक्रमों का समर्थन करते हैं, एमएसएमई विकास को बढ़ावा देते हैं और स्थानीय रोजगार सृजन की सुविधा प्रदान करते हैं। अपने संबोधन में, श्री दुर्लभ दास ने स्थानीय संसाधन क्षमता और बाजार की

जरूरतों के अनुरूप व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए उद्योग विभाग के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने प्रशिक्षुओं को अपनी आजीविका बढ़ाने और सतत सामुदायिक विकास में योगदान देने के लिए स्व–रोज़गार उद्यमों को आगे बढ़ाने के लिए अपने नए अर्जित कौशल का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया।

उद्योग निदेशालय की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम कौशल विकास के माध्यम से ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने, पारंपरिक शिल्प को बढ़ावा देने और द्वीपों में आर्थिक आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाने के लिए प्रशासन की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

एकल–उपयोग प्लास्टिक के विकल्पों पर पांच दिवसीय क्षमता विकास कार्यक्रम 5 फरवरी से

श्री विजय पुरम, 9 जनवरी

सीपीआर पर्यावरण शिक्षा केंद्र (सीपीआरईईसी)–(ईआईएसीपी) द्वारा भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पर्यावरण सूचना, जागरूकता, क्षमता विकास एवं आजीविका कार्यक्रम के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) सदस्यों एवं महिलाओं के लिए "एकल–उपयोग प्लास्टिक के विकल्प के रूप में शिल्प विकास–कचरे से संपदा" विषय पर पाँच दिवसीय क्षमता विकास कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।

यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 5 से 10 फरवरी, 2025 तक सुबह 9 बजे से शाम 3 बजे तक, पार्षद कार्यालय सभागार, वार्ड संख्या–19, भातूबस्ती, श्री विजय पुरम में आयोजित किया जाएगा।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार यह व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम एसएचजी सदस्यों एवं महिलाओं के तकनीकी कौशल को सुदृढ़ करने के साथ–साथ अपशिष्ट सामग्री का उपयोग कर पर्यावरण–अनुकूल शिल्प विकास के माध्यम से सतत आजीविका के अवसरों एवं स्वरोज़गार को प्रोत्साहित करने का उद्देश्य रखता है, जिससे एकल–उपयोग प्लास्टिक के विकल्पों को बढ़ावा दिया जा सके। कार्यक्रम के लिए कुल 50 सीटें उपलब्ध हैं। इच्छुक प्रतिभागी 2 फरवरी, 2025 तक लिंक **https://forms.gle/kWkyCPKYF7wuG62p7** के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी एवं स्पष्टीकरण हेतु प्रतिभागी 9474224389 (व्हाट्सएप)/9933282500 अथवा ई–मेल **cpreecan@gmail.com** पर संपर्क कर सकते हैं।

सूचना, प्रचार और पर्यटन निदेशालय द्वारा प्रकाशित तथा प्रबन्धक, राजकीय मुद्रणालय द्वारा मुद्रित, वितरण तथा विज्ञापन के लिए फोन–229465, प्रधान सम्पादक (प्रभारी) एस. बिजू पिल्लै
e-mail:dweepsamachar@gmail.com

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
सचिवालय

अधिसूचना

श्री विजय पुरम, दिनांक 22 दिसम्बर, 2025

सं. 113/2025/फा.सं. 1–5/हज/2023–राजस्व. – हज समिति नियमावली, 2002 के नियम 20 (1) के साथ पठित हज समिति अधिनियम, 2002 की धारा (2) की उप–धारा (i) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में जारी पूर्व के अधिसूचना का अधिक्रमण करते हुए उप राज्यपाल (प्रशासक), अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह एतद्द्वारा अधोलिखित सदस्यों को नामित कर तत्काल प्रभाव से अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के राज्य हज समिति का पुनर्गठन करते हैं :–

1.	सुश्री वी.के. मरियम बीबी, सुपुत्री वी.एम. कुंजामू, पता : वित यू ऑफिस, ओल्ड एसबीआई बिल्डिंग, बम्बूफ्लैट पी.ओ.–744107, दक्षिण अण्डमान।
2.	श्री ई.पी. मोहम्मद रफीक, सुपुत्र ई.पी. मोहम्मद, फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल के समीप, विम्बर्लीगंज, दक्षिण अण्डमान।
3.	श्री सी.पी. मोहम्मद यूसुफ, सुपुत्र सी.पी. मोइदु, फ्लैट नंबर एस–18, आइलैंड निवास, दिलानीपुर, श्री विजय पुरम।
4.	श्री मोहम्मद सफीक, सुपुत्र स्वर्गीय के. मोहम्मद, मीठाखाड़ी गांव, फरारगंज तहसील, दक्षिण अण्डमान।
5.	श्री टी. अल्वी, सुपुत्र स्वर्गीय टी. मोहम्मद हाजी, 35–मौलाना आजाद रोड, फीनिक्स–बे, श्री विजय पुरम।

इस समिति के सदस्य तत्काल प्रभाव से 03 (तीन) वर्ष की अवधि तक अपने पद पर रहेंगे ।
संघ राज्यक्षेत्र हज कमेटी के कार्यकारी अधिकारी उक्त समिति के पदेन सदस्य होंगे।
अध्यक्ष का चुनाव उपरोक्त सदस्यों में से किया जाएगा।

एडमिरल डी.के. जोशी
पी.वी.एस.एम., ए.वी.एस.एम, वाई. एस. एम, एन.एम., वी.एस.एम. (अ.प्रा.)
उप राज्यपाल (प्रशासक)
अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह।

ह./–
सहायक सचिव (राजस्व)

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
सचिवालय

अधिसूचना

श्री विजय पुरम, दिनांक 23 दिसम्बर, 2025

सं. 114/2025/F.No.M/149/2025-License-Sec-DCSA_AN/E-Comp No.132995- – अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह आनंद विवाह पंजीकरण नियमावली, 2017 के नियम 3 के खंड (क) एवं (ख) के प्रावधानों के अनुसरण में उप राज्यपाल (प्रशासक), अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह एतद्द्वारा अधोलिखित तालिका में दर्शाए गए अधिकारियों को उक्त नियमावली के प्रयोजन हेतु तालिका में उनके समानान्तर वाले कॉलम में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए तत्काल प्रभाव से जिला पंजीकार एवं पंजीकार नियुक्त करते है :–

जिला पंजीकार		
क्रमांक	अधिकारियों का पदनाम	जिला
1.	उपायुक्त	दक्षिण अण्डमान
2.	उपायुक्त	उत्तर तथा मध्य अण्डमान
3.	उपायुक्त	निकोबार
पंजीकार		
क्रमांक	अधिकारियों का पदनाम	क्षेत्र
1.	अपर जिला मजिस्ट्रेट, श्री विजय पुरम	दक्षिण अण्डमान जिला, श्री विजय पुरम
2.	सहायक आयुक्त, डिगलीपुर	डिगलीपुर तहसील
3.	सहायक आयुक्त, मायाबंदर	मायाबंदर तहसील
4.	सहायक आयुक्त, रंगत	रंगत तहसील
5.	सहायक आयुक्त, निकोबार	कार निकोबार
6.	सहायक आयुक्त, ननकौड़ी	ननकौड़ी
7.	सहायक आयुक्त, कैम्पबेल–बे	कैम्पबेल–बे

उप राज्यपाल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

ह./–
सहायक सचिव (राजस्व)
अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन

गणतंत्र दिवस समारोह 2026: वीर गाथा के 5.0 में 1 करोड़ 92 लाख विद्यार्थियों ने भाग लिया

नई दिल्ली, 09 जनवरी।

गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय की एक संयुक्त पहल, प्रोजेक्ट 'वीर गाथा 5.0' को भारी प्रतिक्रिया मिली है। इस वर्ष इस परियोजना में लगभग 1.90 लाख स्कूलों के लगभग 1.92 करोड़ छात्रों ने भाग लिया, जो 2021 में शुरू होने के बाद से अब तक की सबसे अधिक भागीदारी है।

वहीं, राष्ट्रीय स्तर पर 100 विजेताओं का चयन किया गया है प्रारंभिक चरण (कक्षा 3–5) से 25, मध्य चरण (कक्षा 6–8) से 25 और माध्यमिक चरण (कक्षा 9–10 और 11–12 से समान प्रतिनिधित्व) से 50 ।

रक्षा मंत्रालय के अनुसार, 8 सितंबर, 2025 को प्रारंभ की गई वीर गाथा 5.0 में छात्रों की सहभागिता बढ़ाने हेतु नवाचारी विशेषताएं जोड़ी गईं। पहली बार इस पहल में वीडियोग्राफी, एंकरिंग, रिपोर्टिंग और कहानी सुनाने जैसे लघु वीडियो प्रारूपों को शामिल किया गया। इसके माध्यम से छात्रों को भारत की समृद्ध सैन्य परंपराओं, रणनीतियों, अभियानों और वीरतापूर्ण विरासत पर केंद्रित सामग्री तैयार के लिए प्रोत्साहित किया गया।

छात्रों को कलिंग के राजा खारवेल, पृथ्वीराज चौहान, छत्रपति शिवाजी महाराज, 1857 के योद्धाओं और जनजातीय विद्रोहों के नेताओं सहित अन्य महान भारतीय योद्धाओं की अदम्य भावना और सैन्य रणनीतियों का अध्ययन करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया। विषयों की इस विविधता ने न केवल प्रविष्टियों की गुणवत्ता को बढ़ाया, बल्कि प्रतिभागियों की भारत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत की समझ को भी बढ़ाया।

एक महत्वपूर्ण विस्तार के रूप में विदेशों में स्थित सीबीएसई– संबद्ध स्कूलों ने पहली बार इस पहल में भाग लिया। 18 देशों के 91 स्कूलों के 28,005 छात्रों ने अपनी प्रविष्टियां प्रस्तुत कीं, जो भारत की वीरता और राष्ट्रीय गौरव की कहानियों को वैश्विक दर्शकों तक ले जाने में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित हुई और जिसने इस पहल की अंतर्राष्ट्रीय पहुंच को और मजबूत किया।

आपको बता दें, इस परियोजना में स्थानीय स्तर पर विद्यालयों द्वारा गतिविधियां आयोजित करना, वीरता पुरस्कार विजेताओं द्वारा राष्ट्रव्यापी संवाद कार्यक्रम (ऑफ़लाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से) आयोजित करना तथा MyGov पोर्टल के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टियों को जमा करना शामिल था। विद्यालय स्तर की गतिविधियां 10 नवंबर, 2025 को समाप्त हुईं।

वहीं, राज्य और जिला स्तर पर मूल्यांकन के बाद राष्ट्रीय स्तर के मूल्यांकन के लिए लगभग 4,020 प्रविष्टियां प्राप्त हुईं, जिनमें से शीर्ष 100 प्रविष्टियों को सुपर–100 विजेताओं के रूप में चुना गया। इन विजेताओं को नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से सम्मानित किया जाएगा। प्रत्येक विजेता को 10,000 रुपये का नकद पुरस्कार और विशेष अतिथि के रूप में कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड 2026 देखने का अवसर मिलेगा। राष्ट्रीय स्तर के 100 विजेताओं के अतिरिक्त राज्य/केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर आठ विजेताओं (प्रत्येक श्रेणी से दो) और जिला स्तर पर चार विजेताओं (प्रत्येक श्रेणी से एक) का चयन किया जाएगा तथा राज्य/केंद्र शासित प्रदेश/जिला अधिकारियों द्वारा उन्हें सम्मानित किया जाएगा।

गौरतलब हो, परियोजना वीर गाथा की शुरुआत 2021 में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत भारत की स्वतंत्रता की 75 वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में की गई थी। इस पहल का उद्देश्य वीरता पुरस्कार विजेताओं के साहस, उनके वीरतापूर्ण कार्यों और उनकी जीवन यात्राओं को उजागर करना तथा छात्रों में देशभक्ति और नागरिक कर्तव्यबोध की भावना का विकास करना है। पहले संस्करण से लेकर पांचवें संस्करण तक यह परियोजना एक प्रेरणादायक आंदोलन के रूप में विकसित हुई है, जिसकी पहुंच देशभर में ही नहीं, बल्कि विदेशों में स्थित भारतीय स्कूलों तक भी निरंतर बढ़ती गई है।

अपनी शुरुआत के बाद से परियोजना वीर गाथा ने उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। पहले दो संस्करणों में से प्रत्येक में 25 राष्ट्रीय विजेताओं को सम्मानित किया गया, जिसमें पहले संस्करण में लगभग 8 लाख और दूसरे संस्करण में लगभग 19 लाख छात्रों ने भाग लिया। तीसरे संस्करण ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की, जिसमें 100 राष्ट्रीय विजेताओं का चयन किया गया और इसमें 1.36 करोड़ छात्रों की सहभागिता रही, जो वीर गाथा 4.0 में बढ़कर 1.76 करोड़ हो गई।

'सहकार से समृद्धि' की दिशा में ऐतिहासिक बदलाव: 4 वर्षों में सहकारिता मंत्रालय की 114 बड़ी पहलें

नई दिल्ली, 09 जनवरी।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की "सहकार से समृद्धि" की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से 6 जुलाई 2021 को गठित सहकारिता मंत्रालय ने बीते चार वर्षों में सहकारी क्षेत्र को सशक्त, आधुनिक और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कार्य किए हैं। देश के पहले सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में मंत्रालय ने अब तक 114 प्रमुख पहलों को लागू किया है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था, किसानों, महिलाओं, युवाओं और सहकारी संस्थाओं को नया बल मिला है।

पैक्स का कायाकल्प, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती

सहकारिता मंत्रालय ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को बहु–उद्देशीय बनाकर उन्हें ग्रामीण विकास का केंद्र बनाया है। इसके लिए आदर्श उपविधियाँ लागू की गईं, जिन्हें 32 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने अपनाया। इससे पैक्स को डेयरी, मत्स्य, भंडारण, जन औषधि केंद्र, पेट्रोल पंप, LPG वितरण जैसे 25 से अधिक नए व्यवसायों से जोड़ा गया। पैक्स के कम्प्यूटरीकरण की महत्वाकांक्षी योजना के तहत अब तक 59,000 से अधिक पैक्स डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ चुकी हैं। ई–पैक्स के माध्यम से करोड़ों लेन–देन, ऑनलाइन ऑडिट और पारदर्शी लेखा–जोखा संभव हुआ है, जिससे सहकारी व्यवस्था में जनता का भरोसा बढ़ा है।

हर पंचायत में सहकारिता की मौजूदगी

सरकार ने हर पंचायत/गांव में बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों के गठन का लक्ष्य तय किया है। अब तक देशभर में 32,000 से अधिक नई सहकारी समितियाँ पंजीकृत की जा चुकी हैं, जिससे स्थानीय रोजगार और आय के नए अवसर बने हैं।

विश्व की सबसे बड़ी विकेंद्रीकृत अन्न भंडारण योजना

खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी विकेंद्रीकृत अनाज भंडारण योजना शुरू की गई। अब तक 112 पैक्स में गोदाम बनकर तैयार हो चुके हैं, जिनसे 68,000 मीट्रिक टन से अधिक भंडारण क्षमता सृजित हुई है। इससे किसानों को उपज का बेहतर मूल्य और भंडारण की सुविधा मिली है।

राष्ट्रीय स्तर की तीन नई सहकारी संस्थाएँ

निर्यात, बीज और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने तीन नई बहु–राज्य सहकारी समितियाँ गठित कीं।

नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेडः अब तक 13.77 लाख मीट्रिक टन कृषि उत्पादों का निर्यात।

भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेडः 'भारत बीज' ब्रांड के तहत प्रमाणित बीज।

नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेडः 'भारत ऑर्गेनिक्स' ब्रांड से जैविक उत्पादों की देशव्यापी पहचान।

कर सुधार और सहकारी बैंकों को राहत

सरकार ने सहकारी समितियों को कर–प्रणाली में बड़ी राहत दी है–MAT और सरचार्ज में कमी, नकद लेन–देन की सीमा बढ़ाना और नई सहकारी इकाइयों के लिए कम कर दर जैसे कदम उठाए गए। सहकारी बैंकों को नई शाखाएँ खोलने, आवास ऋण बढ़ाने और आधुनिक बैंकिंग सेवाएँ देने की अनुमति दी गई है।

डिजिटल, पारदर्शी और आधुनिक सहकारिता

राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस में 8.4 लाख से अधिक सहकारी समितियों का डेटा शामिल किया गया है। सहकारी रैंकिंग प्रणाली से पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। साथ ही सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए सहकारी विश्वविद्यालय की योजना भी आगे बढ़ रही है।

बीते चार वर्षों में सहकारिता मंत्रालय ने सहकारी आंदोलन को नई ऊर्जा दी है। "सहकार से समृद्धि" अब केवल नारा नहीं, बल्कि गांव–गांव तक पहुंचता विकास मॉडल बन चुका है, जो आने वाले वर्षों में आत्मनिर्भर भारत की नींव को और मजबूत करेगा।

86 प्रतिशत भारतीयों के लिए ज्वेलरी सबसे अहम संपत्ति, नई पीढ़ी तेजी से अपना रही नया ट्रेंडः रिपोर्ट

नई दिल्ली, 09 जनवरी।

भारत में लगभग 86 प्रतिशत लोग सोने और आभूषणों (ज्वेलरी) को संपत्ति बनाने का एक अच्छा साधन मानते हैं। यह संख्या लगभग म्यूचुअल फंड और शेयरों जैसे बाजार से जुड़े निवेश विकल्पों के बराबर है, जिन्हें 87 प्रतिशत लोग पसंद करते हैं। इससे साफ है कि गहनों की अहमियत आज भी बहुत ज्यादा है। बुधवार को जारी डेलॉइट इंडिया की रिपोर्ट में यह बात कही गई है।

डेलॉइट इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, भारत का ज्वेलरी मार्केट तेजी से बदल रहा है। अब लोग आभूषणों को सिर्फ शादी या परंपरा से नहीं जोड़ते, बल्कि अपनी पहचान, जीवनशैली और रोजमर्रा के पहनावे का हिस्सा भी मानते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 56 प्रतिशत लोग ज्वेलरी को, निवेश और फैशन, दोनों के रूप में देखते हैं। वहीं, 28 प्रतिशत लोग केवल निवेश के रूप में गहने खरीदते हैं। इससे पता चलता है कि आभूषणों की भूमिका अब सिर्फ सेविंग्स तक सीमित नहीं रही।

रिपोर्ट के अनुसार, पुरुष और 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोग आभूषणों को ज्यादा निवेश के रूप में खरीदते हैं। वहीं, युवा वर्ग गहनों में स्टाइल, अपने हिसाब से डिजाइन और अलग–अलग तरह से पहनने की सुविधा को ज्यादा महत्व देता है। रिपोर्ट के मुताबिक, जेनजी और युवा पीढ़ी तेजी से हल्के और रोज पहनने वाले गहनों की ओर रुख कर रही है। 51 प्रतिशत जेनजी को चांदी और 34 प्रतिशत को प्लेटिनम वाली ज्वेलरी पसंद है। करीब 49 प्रतिशत लोग हल्के और सादे गहनों को भारी और ज्यादा सजावटी गहनों से ज्यादा पसंद करते हैं।

रिपोर्ट में बताया गया कि 45 प्रतिशत जेनजी और युवा सिल्वर की ज्वेलरी में निवेश करना पसंद करते हैं। इसकी

वजह है अच्छा डिजाइन, कम कीमत और आसानी से खरीदना। अब चांदी को सोने के साथ रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए भी चुना जा रहा है। डेलॉइट इंडिया के अनुसार, पहले भारत में लगभग 70 प्रतिशत गहने शादियों के लिए खरीदे जाते थे, लेकिन अब यह समीकरण बदल रहा है। युवा जन्मदिन और सालगिरह (38 प्रतिशत), रोजाना और ऑफिस में पहनने वाले परिधान (32 प्रतिशत) और पदोन्नति व पढ़ाई जैसी करियर संबंधी उपलब्धियों के लिए आभूषण खरीदते हैं।

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि 49 प्रतिशत लोग अंगूठियां, चेन और कान की बालियां जैसे गहनों को निजी और गैर–धार्मिक मौकों के लिए पसंद करते हैं, जो पारंपरिक भारी गहनों से ज्यादा हैं। हालांकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का असर बढ़ रहा है, लेकिन गहनों के मामले में लोग अब भी दुकान पर जाकर उसे खरीदना ज्यादा भरोसेमंद मानते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, आने वाले समय में आभूषण उद्योग की तरक्की के लिए बेहतर कामकाज, सही योजना और भरोसे पर ध्यान देना सबसे जरूरी होगा।

10 जनवरी की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

नई दिल्ली, 09 जनवरी।

1616 – ब्रिटिश राजदूत सर थॉमस रो ने अजमेर में जहांगीर से मुलाकात की।

1836 – प्रोफेसर मधुसूदन गुप्ता ने अपने चार छात्रों के साथ मिल कर पहली बाद मानव शरीर का विच्छेदन कर आंतरिक संरचना का अध्ययन किया।

1839– भारतीय चाय इंग्लैंड पहुँची।

1863 – लंदन में विश्व की पहली भूमिगत रेल की सेवा शुरू।

1910– पहली एयर मीट हुई।

1912 – ब्रिटिश नरेश जार्ज पंचम और रानी मैरी ने भारत छोड़ा।

1916 – प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूस ने ओटोमन साम्रज्य को हराया।

1920– राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई।

1920– वर्साय संधि के आधिकारिक तौर पर प्रभाव में आने से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ।

1946 – लंदन में संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली बैठक में 51 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

1954 – ब्रिटेन का कॉमेट जेट भूमध्यसागर में दुर्घटनाग्रस्त, विमान में सवार सभी 35 लोग मारे गए। कॉमेट दुनिया का पहला जेट विमान था जिसे ब्रिटेन ने बनाया था।

1963 – भारत सरकार ने स्वर्ण नियंत्रण योजना की शुरुआत की।

1972 – पाकिस्तान में जेल में नौ महीने से अधिक समय तक कैद रहने के बाद बाद शेख मुजीबुर रहमान बंगलादेश पहुंचे।

1991 – संयुक्त राष्ट्र महासचिव जेवियर पेरेज़ द कुइयार खाड़ी युद्ध टालने की अपनी आखिरी कोशिश के तहत इराक की राजधानी बगदाद पहुंचे।

2001 – प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इंडोनेशिया पहुँचे, मेडकाउ बीमारी के प्रति प्रशासनिक लापरवाही के कारण जर्मनी के दो मंत्रियों का इस्तीफ़ा, रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन सोवियत विघटन के बाद पहली बार अजरबैजान पहुँचे।

2002 – ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर पाकिस्तान पहुँचे, इस्रायल के विदेश मंत्री शिमोन पेरेज तीन दिवसीय यात्रा पर भारत पहुँचे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद व नाटो में भारत की सदस्यता का पेरेज ने समर्थन किया, लाल सागर में पकड़े अवैध हथियारों के लिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने फ़िलिस्तीनी नेता यासर अराफात से जवाब मांगा।

2003 – उत्तर कोरिया परमाणु अप्रसार संधि से हटा।

2006– प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह ने 10 जनवरी को प्रति वर्ष विश्व हिन्दी दिवस के रूप मनाये जाने की घोषणा की थी।

2008– कार निर्माण की अग्रणी आटोमोबाइल कंपनी 'टाटा मोटर्स' ने एक लाख रुपये वाली कार नैनो पेश किया। विदेष रेल परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण के मामले में रेल क़ानून, 1989 में संधोधन करने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दी।

2008– इक्वाडोर का तुगंराहो ज्वालामुखी भयानक रूप से फटने के कगार पर पहुँचा।

2009– अशोक कजारिया ने पीएचडी चौंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री का वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद सम्भाला।

2010– भारतीय मूल के अमेरिकी फूड सिक्युरिटी एक्सपर्ट राजीव शाह ने अमेरिका के विदेश मंत्रालय के अधीनस्थ संस्था 'यूएस एजेंसी फॉर इंटरनैशनल डिवेलपमेंट' (यूएसएआईडी) के प्रमुख की ज़िम्मेदारी संभाल ली है। इसके साथ ही वह बराक ओबामा प्रशासन में सर्वोच्च पद संभालने वाले भारतीय बन गए।

2020 – सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू–कश्मीर प्रशासन से संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधान खत्म करने के बाद लगाए गए प्रतिबंधों की एक हते के अंदर समीक्षा करने को कहा।

2020 – ईरान ने घोषणा की कि उसके द्वारा गलती से और अनजाने में एक यूक्रेनी बोइंग 737–800 विमान को निशाया बनाया गया। ईरान ने बयान में कहा कि यह विमान एक संवेदनशील क्षेत्र और सैन्य अड्डे की ओर तेज़ी से मुड़ा था, जिसके कारण हुई मानव–त्रुटि के चलते यह हादसा हुआ।

2020 – ओमान के महामहिम सुल्तान कबूस बिन सैद अल सैद का निधन हो गया। वह 79 वर्ष के थे।

10 जनवरी को क्यों मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस? जानिए पूरा इतिहास

नई दिल्ली, 09 जनवरी।

हिंदी कोई साधारण भाषा नहीं। भारतीयों के लिए हिंदी संस्कृति, भाव और मौन की अभिव्यक्ति का असरदार जरिया है। इस भाषा में मां की मीठी लोरी भी है और आंदोलन की क्रांति की आग भी। हिंदी भाषा के महत्व को समझने, इसके योगदान को सम्मानित करने और दुनियाभर में इसे प्रचारित प्रसारित करने के लिए हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी योग दिवस मनाया जाता है।

वैसे तो हिंदी मूल रूप से भारतीय भाषा है लेकिन अब विश्व मंच पर हिंदी सशक्त भाषा के रूप में स्थापित है। विश्व हिंदी दिवस 2026 भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हमें याद दिलाएगा कि हिंदी अब सीमाओं में नहीं बंधी, वह महाद्वीपों में गूंज रही है। जब कोई विदेशी हिंदी में नमस्ते कहता है, तो वह सिर्फ शब्द नहीं बोलता, वह हमारी सभ्यता को स्वीकार करता है।

विश्व हिंदी दिवस कब है?

इस साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस 2026 मनाया जा रहा है। यह दिन हर वर्ष तय तारीख पर मनाया जाता है और इसका उद्देश्य है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के प्रचार–प्रसार को मजबूती देना है।

विश्व हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत क्यों हुई?

विश्व हिंदी दिवस की नींव 10 जनवरी 1975 को रखी गई, जब नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ। इस ऐतिहासिक सम्मेलन ने यह सिद्ध कर दिया कि हिंदी केवल एक देश की भाषा नहीं, बल्कि वैश्विक संवाद की क्षमता रखने वाली भाषा है। इसी ऐतिहासिक घटना की स्मृति में भारत सरकार ने वर्ष 2006 से 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाने की औपचारिक शुरुआत की। पहला आधिकारिक विश्व हिंदी दिवस पूर्व प्रधानमंत्री

डॉ. मनमोहन सिंह के कार्यकाल में मनाया गया। हालांकि भारत का राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, जो विश्व हिंदी दिवस से अलग है।

राष्ट्रीय हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस में अंतर

यह भ्रम आज भी कई लोगों में है, इसलिए साफ़–साफ़ समझना जरूरी है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन भारत में हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाने की याद में मनाते हैं। तो वहीं विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को वैश्विक मंच पर हिंदी की पहचान और स्वीकार्यता के लिए मनाया जाता है। दोनों का उद्देश्य अलग है, पर आत्मा एक है जो है, हिंदी का सम्मान।

आज विश्व स्तर पर हिंदी की स्थिति

आज हिंदी 190 से ज्यादा देशों में बोली और समझी जाती है, संयुक्त राष्ट्र सहित कई अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सुनी जाती है, बॉलीवुड, ओटीटी, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया ने इसे वैश्विक पहचान दी, प्रवासी भारतीयों ने हिंदी को विदेशों में जीवित ही नहीं, प्रभावशाली बनाया।

विश्व हिंदी दिवस का महत्व

हिंदी शिक्षण संस्थानों को बढ़ावा देना, प्रवासी भारतीयों से सांस्कृतिक जुड़ाव, नई पीढ़ी में हिंदी के प्रति गर्व, डिजिटल युग में हिंदी कंटेंट की ताकत को पहचान दिलाना।

बुनियादी ढांचे के क्रियान्वयन में भारत का PRAGATI मॉडल बना वैश्विक उदाहरण

नई दिल्ली, 09 जनवरी।

ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सईद बिजनेस स्कूल की एक केस स्टडी में भारत के PRAGATI (प्रो–एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन) प्लेटफॉर्म को डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी पहल बताया गया है। दिसंबर 2024 में प्रकाशित और गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से तैयार इस अध्ययन में PRAGATI को देश की बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने का प्रभावी माध्यम बताया गया है।

"From Gridlock to Growth: How Leadership Enables India's PRAGATI Ecosystem to Power Progress" शीर्षक वाली इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मार्च 2015 में लॉन्च होने के बाद से PRAGATI ने 340 से अधिक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा और सामाजिक विकास परियोजनाओं को गति दी है। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत करीब 205 अरब डॉलर बताई गई है।

ऑक्सफोर्ड स्टडी के मुताबिक, PRAGATI ने विभिन्न क्षेत्रों में क्रियान्वयन से जुड़ी बाधाओं को दूर करने और निर्णय प्रक्रिया को तेज करने में केंद्रीय भूमिका निभाई है। यह प्लेटफॉर्म मंत्रालयों और राज्यों के बीच समन्वय बढ़ाकर लंबित परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद करता है।

बोगीबील ब्रिज बना नेतृत्व आधारित निगरानी का उदाहरण

रिपोर्ट में बोगीबील ब्रिज का उदाहरण देते हुए बताया गया है कि शीर्ष स्तर के नेतृत्व और PRAGATI की नियमित समीक्षा से बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को नई गति मिली। अध्ययन के अनुसार, प्रधानमंत्री की सक्रिय निगरानी ने लंबित परियोजनाओं में जवाबदेही और तात्कालिकता का भाव पैदा किया, जिससे संसाधनों का समुचित उपयोग हुआ और जमीनी स्तर पर कार्यरत टीमों को प्रेरणा मिली।

केस स्टडी में बताया गया है कि PRAGATI का एक अहम पहलू स्पष्ट और लागू की जा सकने वाली समयसीमा तय करना है। सड़क, रेलवे, बिजली संयंत्र और पुल जैसी बड़ी परियोजनाएं जटिल लॉजिस्टिक्स और कई एजेंसियों के समन्वय पर निर्भर होती हैं। समयसीमा के अभाव में ये लंबे समय तक अटकी रह सकती हैं।

ऑक्सफोर्ड रिपोर्ट में झारखंड की पकरी–बरवाडीह कोयला खदान परियोजना का उल्लेख किया गया है। वर्ष 2006 में मंजूरी मिलने के बावजूद इस परियोजना में खास प्रगति नहीं हुई थी। 2016 में PRAGATI के तहत समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ने राज्य सरकार को दो महीने में मुआवजा और कानून–व्यवस्था से जुड़े मुद्दे सुलझाने के निर्देश दिए। इसके बाद परियोजना को गति मिली और 2019 में यह पूरी हो सकी।

स्टडी में यह भी बताया गया है कि PRAGATI के जरिए केंद्रीय मंत्रालयों की आंतरिक प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया। वर्ष 2017 में रेलवे मंत्रालय में जनरल अरेंजमेंट ड्रॉइंग्स की मंजूरी में हो रही देरी को एक बड़ी बाधा के रूप में चिन्हित किया गया। इसके बाद तकनीकी समाधान अपनाने के निर्देश दिए गए, जिसके तहत 2020 में इलेक्ट्रॉनिक ड्रॉइंग अप्रूवल सिस्टम शुरू किया गया। इससे मंजूरी की समयसीमा में उल्लेखनीय कमी आई।

ऑक्सफोर्ड विश्लेषण में PRAGATI की एक और खासियत राज्यों और मंत्रालयों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना बताया गया है। एननोर–तिरुवल्लूर–बेंगलुरु–पुदुचेरी–नागपट्टिनम–मदुरै–तूतुकुडी गैस पाइपलाइन परियोजना, जो तीन राज्यों और 400 गांवों से होकर गुजरती है, जनवरी 2024 में पूरी हुई।

रिपोर्ट के अनुसार, 2018 में प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की सरकारों को निर्देश दिया कि भूमि स्वामियों से बातचीत के लिए एक ही क्रियान्वयन एजेंसी को अधिकृत किया जाए। इससे राइट ऑफ वे से जुड़े विवादों का समाधान आसान हुआ और परियोजना समय पर पूरी हो सकी।

नीति विशेषज्ञों का मानना है कि ऑक्सफोर्ड की यह स्टडी इस बात की पुष्टि करती है कि PRAGATI जैसे नेतृत्व आधारित समीक्षा तंत्र जटिल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। रियल–टाइम मॉनिटरिंग और शीर्ष स्तर की निगरानी के जरिए यह प्लेटफॉर्म नौकरशाही की जड़ता को तोड़ने में सफल रहा है।

रिपोर्ट के निष्कर्ष में कहा गया है कि नेतृत्व की सक्रिय भागीदारी और सहयोगात्मक समस्या समाधान पर आधारित PRAGATI का डिजिटल गवर्नेंस मॉडल उन देशों के लिए उपयोगी सबक प्रदान करता है, जो बुनियादी ढांचा क्रियान्वयन में सुधार और विकास के बेहतर परिणाम हासिल करना चाहते हैं।

एआई बूम के बाद 'बाय इंडिया' बन सकता है अगला बड़ा निवेश ट्रेंड

नई दिल्ली, 09 जनवरी।

अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को लेकर बना मौजूदा उत्साह यानी हाइप कम होता है, तो बड़े वैश्विक निवेशकों का ध्यान एक बार फिर भारत की ओर लौट सकता है। इससे भारतीय बाजारों को बड़ा फायदा मिल सकता है। गुरुवार को जारी बे कैपिटल की रिपोर्ट में यह बात कही गई है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनियाभर में एआई से जुड़ा ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर कर्ज लेकर बनाया जा रहा है। यह स्थिति पहले देखे गए टेलीकॉम और फाइबर नेटवर्क बूम जैसी है, जहां शुरुआती तेजी के बाद जोखिम सामने आए थे।

रिपोर्ट के अनुसार, कंपनियों ने जनरेटिव एआई पर 30 से 40 अरब डॉलर का निवेश किया है, लेकिन 95 प्रतिशत संस्थानों को अब तक इससे कोई ठोस लाभ नहीं मिला है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा एआई निवेश माहौल में भारत की बाजार संरचना को एक कमजोरी के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, जब एआई का हाइप खत्म होगा, तब यही बात भारत के लिए फायदे का सौदा साबित हो सकती है।

एआई जैसे अत्यधिक चर्चित विषय में भारत की सीमित भागीदारी भविष्य में असमान लेकिन बड़ा लाभ दे सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक, जब निवेशक फिर से मजबूत आर्थिक आधार पर निवेश फैसले लेंगे, तब भारत को इसका फायदा मिलेगा।

रपोर्ट में बताया गया है कि भारत में अभी सेमीकंडक्टर निर्माण या बड़े डाटा सेंटर जैसे एआई इंफ्रास्ट्रक्चर सीमित हैं। इसके बावजूद भारत तेजी से एआई के उपयोग से

कामकाज को आसान और तेज बनाने वाला देश बनता जा रहा है। इससे बड़े घरेलू बाजार में उत्पादकता और कार्यक्षमता बढ़ रही है।

एआई से जुड़े निवेश के कारण वैश्विक स्तर पर पूंजी का रुख बदला है, जिसके चलते भारत से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) का पैसा बाहर गया है। रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2024 में करीब 23 अरब डॉलर और 2025 में अब तक लगभग 13 अरब डॉलर का विदेशी निवेश भारत से बाहर गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि एआई में निवेश के लिए निवेशकों ने पहले 'सेल इंडिया' का फैसला लिया था, तो एआई का हाइप खत्म होने के बाद 'बाय इंडिया' उनका अगला कदम हो सकता है।रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि विदेशी निवेश के बाहर जाने के बावजूद भारत की आर्थिक स्थिति दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में शामिल बनी हुई है।भारत वैश्विक जीडीपी वृद्धि में 9 प्रतिशत का योगदान देता है। रिपोर्ट के अनुसार, 2025 से 2028 के बीच भारत की अर्थव्यवस्था के 6.7 प्रतिशत से अधिक की दर से बढ़ने की उम्मीद है, जो जी20 देशों में सबसे तेज मानी जा रही है।

इसरो 12 जनवरी को करेगा नए सैटेलाइट का प्रक्षेपण, कृषि और पर्यावरण निगरानी को मिलेगी मजबूती

नई दिल्ली, 09 जनवरी।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) 12 जनवरी 2026 को अपना पहला अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसरो का पीएसएलवी सी62 रॉकेट पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ईओएस एन1 (अन्वेषा) को अंतरिक्ष में स्थापित करेगा।

इसरो ने बताया कि रॉकेट और उपग्रह का इंटीग्रेशन पूरा हो चुका है और प्री–लॉन्च जांच जारी है। यह मिशन 12 जनवरी को सुबह 10:17 बजे श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के पहले लॉन्च पैड से उड़ान भरेगा।

ईओएस एन1 उपग्रह कृषि, शहरी मैपिंग और पर्यावरण निगरानी के लिए भारत की रिमोट सेंसिंग क्षमताओं को मजबूत करेगा।

इस मिशन में ईओएस एन1 के साथ 15 अन्य सह–यात्री उपग्रह भी लॉन्च किए जाएंगे, जिससे यह एक महत्वपूर्ण मल्टी–सैटेलाइट मिशन बन गया है। इसके अलावा, स्पेन की एक स्टार्टअप कंपनी का केस्ट्रेल प्रारंभिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शक भी इस मिशन में शामिल है। यह भविष्य के री–एंट्री वाहन का एक छोटा प्रोटोटाइप है, जिसे कक्षा में भेजने के बाद पृथ्वी के वायुमंडल में वापस लाया जाएगा और दक्षिण प्रशांत महासागर में गिराया जाएगा।

यह मिशन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा संचालित इसरो का 9वां व्यावसायिक (कमर्शियल) मिशन होगा। यह पीएसएलवी की 64वीं उड़ान है और पीएसएलवी–डीएल वेरिएंट का उपयोग करने वाला पांचवां मिशन है।

पीएसएलवी अब तक चंद्रयान–1, मंगलयान, आदित्य–L1 और एस्ट्रोसैट जैसे बड़े मिशन पूरे कर चुका है। 2017 में पीएसएलवी ने एक साथ 104 उपग्रह लॉन्च कर विश्व रिकॉर्ड भी बनाया था।

मोबाइल, पढ़ाई का दबाव और घर का माहौल बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर डाल रहे हैं गहरा असर

नई दिल्ली, 09 जनवरी।

आज के समय में बच्चों की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। पढ़ाई का दबाव, बदलती जीवनशैली, मोबाइल और इंटरनेट की बढ़ती पहुंच, ये सब चीजें बच्चों के मन पर गहरा असर डाल रही हैं। पहले जहां बच्चे खुलकर खेलने में, दोस्तों से बातें करने और परिवार के साथ समय बिताते थे, वहीं अब उनका अधिकतर समय स्क्रीन और प्रतिस्पर्धा के बीच गुजर रहा है।

ऐसे में बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य एक बेहद गंभीर विषय बन गया है, जिस पर ध्यान देना अब केवल जरूरी नहीं बल्कि अनिवार्य हो गया है। मानसिक रूप से स्वस्थ बच्चा ही खुश रहता है, बेहतर सीख सकता है और अपने भविष्य को सही दिशा दे सकता है। इसी कड़ी में यह समझना जरूरी है कि आखिर कौन–सी चीजें बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं और वे कैसे धीरे–धीरे उनके मन और सोच पर असर डालती हैं।

माता–पिता का बर्तावः– बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की नींव माता–पिता का बर्ताव होता है। बच्चा सबसे पहले घर से ही दुनिया को समझना सीखता है। अगर घर का माहौल तनावपूर्ण हो, माता–पिता अक्सर गुस्से में बात करें या बच्चों की बात सुने बिना उन्हें डांट दें, तो बच्चे के मन में डर पैदा होने लगता है।

मनोविज्ञान के अनुसार, ऐसा बच्चा अपनी भावनाओं को दबाने लगता है और खुद को अकेला महसूस करता है। धीरे–धीरे यह डर चिंता और आत्मविश्वास की कमी में बदल सकता है। वहीं, जब माता–पिता प्यार से बात करते हैं, गलती पर समझाते हैं, और बच्चे की बात ध्यान से सुनते हैं, तो बच्चे का मन सुरक्षित महसूस करता है। यह सुरक्षा भावना उसके दिमाग को शांत रखती है और वह खुलकर सोचने व सीखने लगता है।

स्कूल का वातावरणः– बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर स्कूल का वातावरण भी गहरा प्रभाव डालता है। स्कूल

केवल पढ़ाई की जगह नहीं, बल्कि बच्चों की दूसरी दुनिया होता है। अगर स्कूल में हर समय नंबरों की दौड़ हो, तुलना की जाए, या शिक्षक बहुत सख्त रवैया अपनाएं, तो बच्चे के मन में असफल होने का डर बैठ जाता है। यह डर दिमाग में तनाव पैदा करता है, जिससे बच्चा पढ़ाई में मन नहीं लगा पाता।

मनोविज्ञान बताता है कि जब बच्चा खुद को सुरक्षित महसूस करता है, तभी उसका दिमाग बेहतर तरीके से काम करता है। स्कूल का सहयोगी माहौल बच्चों को अपनी गलती से सीखने का मौका देता है, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और मानसिक संतुलन बना रहता है।

स्क्रीन टाइमः– आज के दौर में सोशल मीडिया भी बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला बड़ा कारण बन गया है। सोशल मीडिया पर दिखाई जाने वाली चमक–दमक बच्चों को खुद से तुलना करने पर मजबूर करती है। जब बच्चा दूसरों को ज्यादा अच्छा और ज्यादा सफल देखता है, तो उसके मन में हीन भावना पैदा हो सकती है।

नकारात्मक टिप्पणियां या गलत जानकारी उसके सोचने के तरीके को बिगाड़ सकती हैं। मनोविज्ञान के अनुसार, बच्चों का दिमाग पूरी तरह विकसित नहीं होता, इसलिए वे ऑनलाइन चीजों को सच मान लेते हैं। इससे भ्रम, डर और उदासी जैसी भावनाएं जन्म ले सकती हैं।

नए कानून में 100 प्रतिशत एफडीआई की मंजूरी और रीइंश्योरेंस में राहत से भारत के बीमा सेक्टर को मिलेगी मजबूती

नई दिल्ली, 09 जनवरी।

नए कानून में 100 प्रतिशत एफडीआई की मंजूरी और रीइंश्योरेंस में राहत से भारत के बीमा सेक्टर को मिलेगी मजबूती संसद द्वारा बीमा कानून (संशोधन) विधेयक, 2025 को मंजूरी मिलने के बाद भारत के बीमा क्षेत्र को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। इस नए कानून से अब बीमा कंपनियों में 100 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की अनुमति मिल गई है और वैश्विक पुनर्बीमा कंपनियों के लिए नियम भी आसान कर दिए गए हैं।

इंश्योरेंस एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक, इन सुधारों से बीमा कंपनियों को पूंजी आसानी से मिलेगी, उनकी वित्तीय मजबूती बढ़ेगी और बाजार में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी। इससे खासतौर पर छोटी और मध्यम बीमा कंपनियों को फायदा होगा और पूरा बीमा तंत्र मजबूत बनेगा। इस विधेयक के तहत बीमा कंपनियों में विदेशी निवेश की सीमा को 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके लिए इस क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कानूनों में बदलाव किए गए हैं, जिनमें बीमा अधिनियम, 1938, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 और बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) अधिनियम, 1999 में बदलाव किए गए हैं।

नया नियम ऐसे समय में लाया गया है जब बीमा कंपनियों के लिए पूंजी से जुड़े नियम सख्त हो रहे हैं। अधिक विदेशी निवेश से कंपनियों पर धन की कमी का दबाव कम होगा और वे बेहतर तरीके से काम कर पाएंगी। केयरएज रेटिंग्स के अनुसार, इस सुधार से बीमा कंपनियों के आपस में जुड़ने और मजबूत बनने की प्रक्रिया को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे बीमा क्षेत्र और ज्यादा स्थिर हो सकेगा।

विधेयक में एक और बड़ा बदलाव किया गया है। अब विदेशी पुनर्बीमा कंपनियों के लिए जरूरी न्यूनतम पूंजी

को 5,000 करोड़ रुपए से घटाकर 1,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इससे अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के लिए भारत में आना आसान हो जाएगा। इस फैसले से देश के अंदर पुनर्बीमा की क्षमता और प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया है कि जरूरी पूंजी भारत में ही रहे, जिससे स्थानीय बीमा कंपनियों को फायदा मिल सके।

इस बीच, एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज की एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही में बीमा क्षेत्र का कामकाज संतोषजनक रहने की उम्मीद है। हालांकि, बीमा प्रीमियम में बढ़ोतरी होगी, लेकिन जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) घाटे, ज्यादा कमीशन और नियमों में बदलाव के चलते मुनाफे पर दबाव बने रहने की उम्मीद है।

पिछले महीने उद्योग संगठनों ने इस विधेयक की सराहना करते हुए कहा कि यह कदम बीमा क्षेत्र में स्पष्टता, भरोसा और लंबे समय तक पूंजी लाएगा, जिससे लोगों की वित्तीय सुरक्षा और मजबूत होगी। इस विधेयक में विशेष आर्थिक क्षेत्रों और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में काम करने वाली बीमा कंपनियों को ज्यादा छूट दी गई है। अब केंद्र सरकार इन क्षेत्रों के लिए अलग बीमा नियम बना सकेगी, जिससे अंतरराष्ट्रीय बीमा गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

खबरों और रोचक जानकारियों के लिए पढ़िए
'द्वीप समाचार'